



भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 34] नई दिल्ली, शनिवार, अगस्त 25—अगस्त 31, 2018 (भाद्र 3, 1940)
No. 34] NEW DELHI, SATURDAY, AUGUST 25—AUGUST 31, 2018 (BHADRA 3, 1940)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

| पृष्ठ सं. | विषय-सूची | पृष्ठ सं. |
|---|-----------|--|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं..... | 559 | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं..... * |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 607 | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... * |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 13 | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश..... * |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं..... | 1893 | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... 8391 |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम..... | * | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस..... * |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ..... | * | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं..... * |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट..... | * | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं..... 1929 |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)..... | * | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस..... 1763 |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को | | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्ण..... * |

*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

CONTENTS

| | Page No. | | Page No. |
|--|-------------|---|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 559 | by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court | 607 | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) | * |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence..... | 13 | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence | * |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence | 1893 | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India | 8391 |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs | * |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations | * | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners | * |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills | * | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies | 1929 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) | * | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies | 1763 |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and | | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi | * |

*Folios not received.

भाग I—खण्ड 1
[PART I—SECTION 1]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय

(उच्चतर शिक्षा विभाग)

[यू.3(ए) अनुभाग]

नई दिल्ली, 8 अगस्त, 2018

सं.एफ.9/15/93-यू.3 (पार्ट.1).—**जबकि**, केन्द्र सरकार को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) अधिनियम, 1956 की धारा 3 के तहत यूजीसी की सलाह पर किसी उच्चतर शिक्षा संस्था को समवत विश्वविद्यालय घोषित करने की शक्ति प्राप्त है।

2. **और जबकि**, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम, 1956 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्ति का उपयोग करते हुए यूजीसी की सलाह पर दिनांक 29.09.1994 की अधिसूचना सं.9-15/93-यू.3 के माफत श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, मद्रास को, कुछ शर्तों के साथ समविश्वविद्यालय संस्था के रूप में घोषित किया है।

3. **और जबकि**, रजिस्ट्रार, श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान, चेन्नई ने दिनांक 25.11.2017 को “श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज एवं अनुसंधान संस्थान” का नाम बदलकर “श्री रामचंद्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” करने का अनुरोध प्रस्तुत किया था।

4. **और जबकि**, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने दिनांक 16.02.2018 के अपने पत्र सं.9-15/93-यू.3(पार्ट-1) के माफत निम्नलिखित शर्तों के अध्याधीन संस्थान का नाम बदलने के लिए अपनी सैद्धांतिक अनुमोदन प्रदान किया था :-

- i विशिष्ट और विशेष समिति/ट्रस्ट/कंपनी को संशोधित नाम से पंजीकृत किया जाएगा।
- ii सभी परिसंपत्तियां (सचल एवं अचल) कानूनी रूप से नए प्रस्तावित नाम पर अंतरित की जाएगी।
- iii समग्र निधि नए नाम पर अंतरित की जाएगी।
- iv संस्था यूजीसी (समविश्वविद्यालय संस्थाएं) विनियम, 2016 के अनुसरण में अपने एमओए/नियम तैयार करेगी।

5. **और इसके अतिरिक्त जबकि**, संस्था ने उपरोक्त उल्लिखित शर्तों के संबंध में अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत की थी जिसकी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सत्यापन किया गया था।

6. **अब इसलिए**, केन्द्र सरकार ने यूजीसी अधिनियम 1956 की धारा 3 में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, यूजीसी की सलाह पर, इस अधिसूचना के जारी होने के संदर्भ में, एतद्वारा श्री रामचंद्र मेडिकल कॉलेज और अनुसंधान संस्थान का नाम बदलकर “श्री रामचंद्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान” कर दिया है। श्री रामचंद्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पोरूर, चैन्नई, अपने नाम के साथ “विश्वविद्यालय” प्रत्यय शब्द प्रयोग नहीं करेगा परंतु इसके आगे कोष्ठक में “समविश्वविद्यालय” शब्द का उल्लेख कर सकता है।

7. इस मंत्रालय की पूर्व अधिसूचना में उल्लिखित सभी अन्य शर्तों के साथ-साथ यूजीसी और संबंधित सांविधिक परिषद द्वारा समय-समय पर जारी मानकों/विनियमों का श्री रामचन्द्र उच्चतर शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, पोरूर, चेन्नई द्वारा यथावत् पालन किया जाएगा।

ईशिता राय
संयुक्त सचिव

वस्त्र मंत्रालय

नई दिल्ली, 2 अगस्त, 2018

संशोधित संकल्प

दिनांक फरवरी 29, 2016 के समसंख्यक जीआर का अधिक्रमण करते हुए

सं2015/5/6 .टीयूएफएस.— संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के 13.01.2016 मंत्रालय के दिनांकवस्त्र (एटीयूएफएस) 13.01.2016 के अनुसार एटीयूएफएस के दिशानिर्देश अर्थात् दिनांक संकल्प से अधिसूचित की गयी है। उक्त के माध्यक संकल्पसमसंख्यसे नुसार यन तंत्र निम्नांक मानदंड तथा क्रियान्वय और प्रचालनात्मयन अवधि के दौरान एटीयूएफएस के वित्तीयतक इसके क्रियान्व 31.03.2022 :-निर्धारित किए गए हैं

.1 उद्देश्य :

1.1 देश में व्यवसाय को आसान बनाने और विनिर्माण में 'जीरो इफेक्ट और जीरो डिफेक्ट' के साथ 'मेक इन इंडिया' के माध्यम से रोजगार का सृजन करने तथा निर्यात को बढ़ावा देने के दृष्टिकोण को प्राप्त करने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है कि सरकार, संशोधित प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना से जुड़ा ऋण प्रदान करेगी। (सीआईएस) के अंतर्गत पूंजी निवेश सब्सिडी (एटीयूएफएस)

1.2 यह योजना वस्त्र उद्योग में आयात विकल्प के साथ निवेश, उत्पादकता, गुणवत्ता, रोजगार, निर्यात को बढ़ावा देने को सुविधाजनक बनाएगी। यह वस्त्र मशीनरी क्ष रूप से निवेश को भी बढ़ावा देगी। के निर्माण में अप्रत्य (बेंचमार्क प्रौद्योगिकी वाली)

.2 योजना के अधीन परिभाषाएं

2.1 प्रौद्योगिकी उन्नयन का तात्पर्य वस्त्र उद्योग के किसी कंपनी द्वारा ऐसी अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी मशीनरी को लगाना है जिसे तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) द्वारा वार्षिक आधार पर निर्दिष्ट किया गया है। निर्दिष्ट सीमा से कम प्रौद्योगिकी स्तर वाली मशीनरी को प्रौद्योगिकी उन्नयन के रूप में नहीं माना जाएगा।

2.2 पूंजी निवेश सब्सिडी: (सीआईएस) का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के संबंध में वस्त्र क्षेत्र में कार्य कर रही किसी कंपनी को पूंजी निवेश संबद्ध ऋण पर निर्धारित दर पर सब्सिडी देना है जिसका निर्धारण इसे स्थापित और शुरू किए जाने के बाद विनिर्दिष्ट मशीनरी की मूल लागत के आधार पर किया जाएगा।

2.3 मूल लागत का तात्पर्य कर, शुल्क और किसी अन्य प्रभार को छोड़कर मशीनरी की लागत से है।

2.4 कंपनी का तात्पर्य वस्त्र उत्पादों का विनिर्माण कर रहे निम्नलिखित से हैं :

- i. समय-समय पर यथासंशोधित कंपनी अधिनियम, 1956 के तहत पंजीकृत कंपनिया या
- ii. समय-समय पर यथासंशोधित एलएलपी अधिनियम, 2008 के तहत पंजीकृत लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप फर्म से है या
- iii. समय-समय पर यथासंशोधित एमएसएमई अधिनियम के तहत पंजीकृत लघु और मध्यम उद्यमों से है या
- iv. जिन कंपनियों का औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग के साथ औद्योगिक उद्यमशीलता का ज्ञापन (आईईएम) है या
- v. जो इकाइयां राज्य सरकार के संबंधित निदेशालयों में पंजीकृत हैं।

- 2.5 ऋणदाता एजेंसी में आरबीआई में पंजीकृत और टीएएमसी द्वारा अधिसूचित सार्वजनिक क्षेत्र के सभी बैंक, राज्य वित्तीय निगम (एसएफसी), राज्य औद्योगिक विकास निगम (एसआईडीसी), अनुसूचित बैंक, सहकारी बैंक और एनबीएफसी शामिल हैं।
- 2.6 गार्मेंटअप्स-मेड/अपैरल/ का तात्पर्य पहनने योग्य अथवा गैरसिलाए फैब्रिक से है जिसके कम से कम दो किनारों - सिलेपहनने योग्य-को सिलाई मशीन का प्रयोग करके सिला गया हो।
- 2.7 तकनीकी वस्त्र का तात्पर्य ऐसी वस्त्र सामग्री और उत्पादों से है जिनका प्राथमिक उपयोग मुख्यतया उनके तकनीकी निष्पादन और कार्यात्मक गुणों के लिए किया गया हो और इसमें एग्रेटेक्स, मेडिटेक्स, मोबिलिटेक्स, पैकटेक्स, स्पोर्टेक्स, बिल्डटेक्स, क्लोदटेक्स, होमटेक्स, प्रोटेक्स, जियोटेक्स, ओएकोटेक्स और इंडुटेक्स आदि शामिल हैं।
- 2.8 विशिष्ट पहचान संख्या (यूआईडी) का तात्पर्य प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए विनिर्दिष्ट मशीनरी के अनंतिम अनुमानों के आधार पर अनुमानित पूंजी निवेश सब्सिडी के अनंतिम अनुमोदन से है। (सीआईएस)
- 3. पूंजी निवेश सब्सिडी के लिए पात्रता**
- 3.1 निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी उन्नयन पर निवेश के लिए केवल इकाइयों को पूंजी निवेश सब्सिडी उपलब्ध होगी। (सीआईएस)
- क) विविंग, विविंग प्रीपेरेटरी और निटिंग
 - ख) फाइबर की प्रोसेसिंग, यार्न, फैब्रिक्स, गार्मेंट और मेड-अप्स
 - ग) तकनीकी वस्त्र
 - घ) गार्मेंट/मेड-अप्स निर्माण
 - ङ) हथकरघा क्षेत्र
 - च) रेशम क्षेत्र
 - छ) पटसन क्षेत्र
- 3.2 उपर्युक्त सभी क्षेत्रों के लिए मशीनरी प्रौद्योगिकी विनिर्देशन तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति क द्वारा प्रत्ये (टीएएमसी) 1 वर्ष अप्रैल से अग्रिम रूप से निर्धारित किया जाएगा।
- 3.3 मशीन विनिर्माता अथवा उनके प्राधिकृत एजेंटों/आपूर्तिकर्ताओं से सीधे खरीदी गई मशीन इस योजना के अंतर्गत पूंजी निवेश की पात्र / होगी।
- 3.4 उद्योग की सुविधा के लिए टीएएमसी उन मशीनों के विनिर्माताओं की संकेतात्मक सूची भी प्राप्त करेगी जो पैरा 3.2 में निर्धारित प्रौद्योगिकी के विनिर्देशनों के अनुरूप हों और जिसके लिए तकनीकी समिति की सहायता ली जाएगी जिसमें उद्योग के सदस्य और विशेषज्ञ होंगे जिसकी अध्यक्षता वस्त्र आयुक्त के कार्यालय में सबसे वरिष्ठ तकनीकी अधिकारी करेंगे। इस समिति का गठन वस्त्र आयुक्त करेंगे। यह संकेतात्मक सूची, आम जनता की सूचना और टिप्पणी/सुझाव देने के लिए वेब साइट पर रखी जाएगी जिसे अंततः टीएएमसी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। यह समिति ऐसी मशीनों और विनिर्माताओं की सूची को अद्यतन करने के लिए मासिक बैठक करेगी।
- 3.5 उपर्युक्त 3.2 विनिर्दिष्ट स्तर से कम प्रौद्योगिकी वाली मशीनरी इस योजना के तहत सब्सिडी की पात्र नहीं होगी। तथापि, उपर्युक्त पैरा पक या पूर्ण नहीं की होगी और इसे व्यापक तहत तैयार की गई विनिर्माताओं और मशीनरी की सूची केवल सुझावात्मक 3.3 माना जाएगा। उद्योग ऐसी मशीनरी की खरीद करने के लिए स्वतंत्र है जो विनिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी पैरामीटरों के अनुरूप हो। ऐसे मामलों में उपर्युक्त पैरा उल्लिखित तकनीकी समिति में 3.4, उन विनिर्माताओं और मशीनरी को सत्यापित करेगी और यदि उसे उपयुक्त पाया जाता है तो टीएएमसी विनिर्माताओं की संकेतात्मक सूची में उन्हें शामिल किए जाने का प्रस्ताव करेगी।
- 3.6 जेआईटी के अनुप्रयोग, पैरा 3.2 में यथानिर्धारित प्रौद्योगिकी विनिर्देशनों का मिलान करने पर किया जाएगा लेकिन तैयार की गई संकेतात्मक सूची में शामिल और 3.3 तथा 3.4 के तहत अद्यतन की गई विनिर्माता और मशीनरी की सूची के आधार पर सब्सिडी का संवितरण किया जाएगा।
- 3.7 इस योजना के तहत सेकेंड हैंड मशीनरी सब्सिडी के लिए पात्र नहीं होगी।

- 3.8 मशीनरी की मूल लागत के **20%** मूल्य तक मशीनरी के साथ प्राप्त या संकेतात्मक सूची में सूचीबद्ध दूसरे विनिर्माताओं से खरीदी गई सहायक सामग्री/अटैचमेंट/नमूना मशीनें/अतिरिक्त कल-पुर्जे भी सब्सिडी के पात्र होंगे।
- 3.9 एक सेगमेंट के लिए पात्र मशीनरी दूसरे सेगमेंट (सेगमेंटों)/क्रियाकलाप(क्रियाकलापों) के लिए भी पात्र है, यदि इसके पात्रता किसी विशेष सेगमेंट/क्रियाकलाप के लिए विशेष रूप से प्रतिबंधित न हो।
- 3.10 इकाई का विलय किए जाने, अधिग्रहण, मिलाए जाने या दूसरे निकाय को अंतरित किए जाने के मामले को छोड़कर टीयूएफएस के तहत सब्सिडी से खरीदे गए संयंत्र और मशीनरी का निपटान वस्त्र आयुक्त के पूर्व अनुमोदन के बगैर खरीदी गई तारीख से **10 वर्ष** पहले नहीं किया जाएगा।
4. सब्सिडी के लिए मानक:
- 4.1 इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक पात्र व्यक्तिगत कंपनी (यूनिट नहीं) नीचे निर्दिष्ट दरों के अनुसार पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र होगी:

| क्र.सं. | क्षेत्र | पूंजी निवेश सब्सिडी की दरें (सीआईएस) |
|---------|--|---|
| 1. | परिधान, तकनीकी वस्त्र | करोड़ रुपए की उच्च 30 धीनसीमा के अद्य 15% |
| 2. | एकदम नए शटलप्रीपेरेटरी बुनाई एवं निटिंग) रहित करघों के लिए बुनाई- (सहित, प्रसंस्करण, पटसन, रेशम और हथकरघा | करोड़ रुपए की उच्च 20 धीनसीमा के अद्य 10% |
| 3(क) | मिश्रित इकाई श्रेणी के यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र -पल क्षेत्रोंमल्टी/ संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से अधिक है। | करोड़ रुपए की उच्च 30 धीनसीमा के अद्य 15% |
| 3(ख) | मिश्रित इकाई श्रेणी के यदि परिधान एवं तकनीकी वस्त्र -पल क्षेत्रोंमल्टी/ संबंध में पात्र पूंजी निवेश पात्र परियोजना लागत के 50% से कम है। | करोड़ रुपए की उच्च 20 धीनसीमा के अद्य 10% |

- 4.2 यदि आवेदक ने आरआरटीयूएफएस के अंतर्गत पहले ही सब्सिडी प्राप्त कर ली है तो वह व्यक्तिगत कंपनी के लिए निर्धारित समग्र सीमा के भीतर नई या मौजूदा इकाइयों के लिए शेष राशि का ही पात्र होगा।
- 4.3 यह ऋण से जुड़ी योजना है। जब कोई कंपनी किसी अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी से परियोजना के तहत कुल पात्र मशीनरी की लागत का कम से कम 50% आवधिक ऋण प्राप्त करेगी तो वह पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने की पात्र होगी।
- 4.4 यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि निर्धारित सीमा के अंदर ही सब्सिडी प्राप्त हो इसके लिए कंपनी को आरआरटीयूएफएस और एटीयूएफएस के तहत उसके द्वारा प्राप्त की गई सब्सिडी की घोषणा करनी होगी।
- 4.5 संतोषजनक ढंग से मशीनरी लगाए जाने/शुरू किए जाने और उत्पादन आरंभ होने के बाद पात्र निवेश पर कंपनी को एक बार ही पूरी पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) जारी की जाएगी।
5. पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने के लिए आवधिक ऋण के मानदंड:
- 5.1 आवधिक ऋण किसी अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी द्वारा मंजूर किया जाएगा। दिनांक 04.10.2013 के संकल्प सं. 6/19/2013-टीयूएफएस के अनुसार आरआरटीयूएफएस में शामिल ऋणदाता एजेंसियां स्वतः ही इस योजना में शामिल हो जाएंगी और नई ऋणदाता एजेंसियों को आई-टीयूएफएस साफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त, मुंबई को अनुबंध-क के अनुसार निर्धारित फार्मेट में अपना आवेदन प्रस्तुत करना होगा ताकि एटीयूएफएस के तहत ऋणदाता एजेंसी को अधिसूचित किया जा सके।
- 5.2 यह ऋण से जुड़ी योजना है। जब कोई कंपनी किसी अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी से परियोजना के तहत कुल पात्र मशीनरी की लागत का कम से कम 50% आवधिक ऋण प्राप्त करेगी तो वह पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) प्राप्त करने की पात्र होगी।

- 5.3 इस योजना के तहत किसी परियोजना के लिए कोई गुणक वित्तीय सहायता नहीं दी जाएगी। इस संबंध में लाभार्थी को अनुबंध-ख के अनुसार निर्धारित फॉर्मेट में वचनपत्र देना होगा।
- 5.4 योजना के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए स्वीकृत आवधिक ऋण की वापसी अदायगी की न्यूनतम अवधि तीन वर्ष होगी जिसमें एमएसएमई इकाइयों के लिए अधिस्थगन काल शामिल है तथा अन्य श्रेणियों के लिए न्यूनतम 5 वर्ष होगी।
- 5.5 जिस इकाई के लिए ऋण लिया गया है वह कम से कम ऊपर विनिर्दिष्ट आवधिक ऋण की वापसी अदायगी अवधि के दौरान काम करेगी।
- 5.6 विदेशी मुद्रा ऋण: विदेश स्थित किसी भारतीय बैंक की शाखा/भारत में शाखा वाले किसी विदेशी बैंक से लिया गया विदेशी मुद्रा ऋण इस योजना के लाभ प्राप्त करने का पात्र होगा। तथापि, ऋण खाता भारतीय शाखा से भी चलाया जाना चाहिए ताकि भारतीय शाखा में आवेदक के खाते में भारतीय रुपए में सब्सिडी की राशि अंतरित की जा सके। भारतीय रुपया ऋण (आरटीएल) को विदेशी मुद्रा ऋण (एफसीएल) और विलोमतः परिवर्तित करने की अनुमति है।
- 5.7 ऋण का बकाया मूलधन इस शर्त के अधीन एक ऋणदाता एजेंसी से दूसरी ऋणदाता एजेंसी को अंतरित किया जा सकता है कि पोर्टफोलियो अपरिवर्तित रहे।
- 6 स्वीकृति की तारीख:
- 6.1 स्वीकृति की तारीख ऋण प्रदान करने वाली एजेंसी के पत्र की वह तारीख होगी जिसके माध्यम से ऋण की स्वीकृति की सूचना कंपनी को दी गयी है।
- 6.2 यदि ऋणदाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृत कर दिया जाता है और उसके बाद ऋणदाता एजेंसी ने आवधिक ऋण को अन्य ऋणदाता एजेंसी(यों) को वितरित/डाउन सेल कर दिया है अथवा कंसोर्टियम फाइनेन्स के अंतर्गत आवधिक ऋण स्वीकृत कर दिया है, आवधिक ऋण स्वीकृत की तारीख निम्नानुसार होगी:
- (i) आवधिक ऋण को डाउन-सेल करने के मामले में प्रथम ऋणदाता एजेंसी, जिसने आरम्भ में आवधिक ऋण स्वीकृत किया है, द्वारा आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख संगत तारीख होगी।
- (ii) कंसोर्टियम फाइनेन्स के मामले में कंसोर्टियम में पिछली ऋणदाता एजेंसी की ऋण स्वीकृति पत्र की तारीख संगत तारीख होगी।
- 6.3 उपर्युक्त प्रत्येक मामले में यथानुपात आधार पर प्रत्येक ऋणदाता एजेंसी में रखे गए कंपनी के खाते में पूंजी निवेश सब्सिडी (सीआईएस) का संवितरण किया जाएगा।
- 6.4 जिन आवेदकों ने अंतिम तारीख अर्थात् 12 जनवरी, 2016 से पहले आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में आरआर-टीयूएफएस के अंतर्गत यूआईडी के लिए आवेदन किया है किंतु उन्हें निधियों की उपलब्धता नहीं होने के कारण यूआईडी जारी नहीं की जा सकी, उनको एटीयूएफएस के अंतर्गत सब्सिडी के लिए आवेदन करने हेतु एक अवसर प्रदान किया जाएगा। वे वस्त्र आयुक्त से इस संबंध में सूचना प्राप्त होने के एक महीने के भीतर ऑनलाइन इस विकल्प का प्रयोग कर सकेंगे।
- 7 ऋण की स्वीकृति से पहले निवेश का कवरेज:
- 7.1 आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख से पूर्व आवेदक द्वारा मशीन की लागत में अपनी हिस्सेदारी की सीमा तक अग्रिम भुगतान किया जा सकता है।
- 7.2 आवधिक ऋण की स्वीकृति की तारीख को अथवा उसके बाद खरीदी गयी मशीनें ही सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
- 7.3 खरीद की तारीख, बैंक द्वारा लेने देन के विवरण अथवा वाणिज्यिक बीजक की तारीख, जो भी बाद की हो, सबूत के रूप में मशीनरी के लिए कंपनी द्वारा किए गए पूर्ण और अंतिम भुगतान की तारीख होगी।
- 8 अन्य योजनाओं के अंतर्गत स्वीकार्य लाभ:
- वस्त्र इकाइयों को इस योजना के अंतर्गत प्रदान किए गए लाभ के अलावा, राज्य सरकार की योजनाओं के लाभ प्राप्त करने की अनुमति है।

9 कंपनी के प्रबंधन का विलय/अधिकार में लेना:

कंपनियों के विलय अथवा किसी दूसरी कंपनी द्वारा कंपनी को अधिकार में लेने के मामले में नई कंपनी इस योजना के अंतर्गत इस शर्त के अधीन सन्निडी की शेष राशि, यदि कोई बकाया हो, प्राप्त करने की हकदार होगी, यदि विलय/अधिकार में लेने की अनुमति या तो कंपनियों के पंजीयक द्वारा अथवा माननीय न्यायालय के आदेश द्वारा दी गई है और नई कंपनी ने विलय/अधिकार में ली गयी कंपनी की सभी देयताओं और परिसम्पत्तियों को अधिकार में ले लिया है और संबंधित बैंक ने भी मौजूदा कंपनी जिसने उसे अधिकार में लिया है, पूर्ववर्ती कंपनी के नाम का आवधिक ऋण भी अंतरित कर दिया है। ऐसे मामलों में नई कंपनी आईएटीयूएफएस साफ्टवेयर के माध्यम से विलय की गयी कंपनी का प्रोफाइल परिवर्तित करने के लिए सभी सहायक दस्तावेजों के साथ अनुबंध 'ग' के अनुसार निर्धारित प्रपत्र में वस्त्र आयुक्त को आवेदन प्रस्तुत करेगी।

10. क्रियान्वयन का तंत्र:

इस योजना को आई-टीयूएफएस नामक वेब आधारित सक्षम सॉफ्टवेयर के माध्यम से वस्त्र आयुक्त द्वारा क्रियान्वित किया जाएगा। योजना के क्रियान्वयन में शामिल किए गए उपायों को नीचे दर्शाया गया है:

10.1 यूआईडी प्राप्त करने की प्रक्रिया:

10.1.1 कंपनी अपने प्राधिकृत आवेदक के माध्यम से ई-मेल, मोबाइल नम्बर और पैन के विवरण के साथ आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में पंजीकृत होगी।

10.1.2 आवेदक सिस्टम में यथा-अपेक्षित सूचना को भरेगा और ए-टीयूएफएस के अंतर्गत अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी से आवधिक ऋण के लिए आवेदन करेगा।

10.1.3 आई-टीयूएफएस के सूचना पृष्ठ में अधिसूचित ऋणदाता एजेंसियों की सूची दी जाएगी और यह आई-टीयूएफएस के पोर्टल के आवेदन पृष्ठ के ड्रॉप-डाउन मैन्यू में भी उपलब्ध होगा। ऋण के लिए आवेदन करते समय निम्नलिखित सुनिश्चित किया जाएगा:

- i. ऋण की अवधि एमएसएमई इकाइयों के लिए गिरवी की अवधि सहित तीन वर्ष और अन्य श्रेणियों वाली कंपनियों के लिए 5 वर्ष होगी।
- ii. ऋण कुल पात्र मशीनरी की लागत का न्यूनतम 50% होगा। सभी क्षेत्रों के लिए पात्र प्रौद्योगिकी की निर्धारित विशिष्टता सूची आई-टीयूएफएस के पोर्टल के ड्रॉप-डाउन मैन्यू में उपलब्ध होगी। इसके अलावा, निर्दिष्ट सूची से बाहर मशीनरी की खरीद को समाहित करने के लिए अन्य प्रावधान के साथ-साथ ड्रॉप-डाउन मैन्यू में विनिर्माताओं की निर्दिष्ट सूची भी उपलब्ध होगी।
- iii. चूंकि यह सूची बदलती रहती है, टीएमसी इसे हर महीने अद्यतन करेगी और यह सूची परिवर्तनशील होगी, सॉफ्टवेयर की टीम, टीएमसी के निर्णयों के अनुसार साथ ही हर महीने इस सूची को अद्यतन करती रहेगी।

10.1.4 आवेदन को आवेदक के डिजिटल हस्ताक्षर/आधार आधारित ई-हस्ताक्षर के साथ हस्ताक्षरित किया जाएगा। आवेदन के लिए एक ए-टीयूएफएस संदर्भ संख्या तैयार की जाएगी और मोबाइल नं. तथा ई-मेल पर इसकी सूचना दी जाएगी।

10.1.5 आवेदन, एसएमएस और ई-मेल ट्रिगर के साथ ऋणदाता एजेंसी के इन-बॉक्स में प्राप्त किया जाएगा। ऋणदाता एजेंसी अपने मानदंडों के अनुसार प्रस्ताव की जांच करेगी और यदि परियोजना को व्यवहार्य पाया जाएगा तो दिशानिर्देशों के पैरा 5 में उल्लेख किए गए अनुसार ए-टीयूएफएस के अंतर्गत वित्तीय मानदंडों को ध्यान में रखते हुए आवधिक ऋण को स्वीकृत करेगी।

10.1.6 ऋणदाता एजेंसी आई-टीयूएफएस में आवधिक ऋण की सूचना का विवरण भरेगी और ऋणदाता एजेंसी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ अंतिम स्वीकृत पत्र की प्रति अपलोड करेगी। आवधिक ऋण की स्वीकृति के बारे में कंपनी को एक एसएमएस और ई-मेल भेजा जाएगा।

10.1.7 ऋण की स्वीकृति के पश्चात आवेदन वस्त्र आयुक्त के इन-बॉक्स में पहुंचेगा और स्वतः यूआईडी तैयार हो जाएगी। कंपनी को उनके पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नं. पर यूआईडी के बारे में सूचित किया जाएगा।

10.1.8 ऋण आवेदन निरस्त किए जाने के मामले में कंपनी को उनके पंजीकृत पत्र-व्यवहार के पते पर इसकी सूचना भेजी जाएगी। इस स्तर पर कोई शिकायत सीधे ऋणदाता एजेंसी को की जा सकेगी। वस्त्र आयुक्त, ऋणदाता एजेंसियों से संबंधित किन्हीं शिकायतों के लिए जिम्मेदार नहीं होगा।

- 10.1.9 ऋणदाता एजेंसी, आवेदन प्राप्त होने के चार महीने के भीतर आवधिक ऋण को स्वीकृत करने की प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगी। ऋणदाता एजेंसी को हर पखवाड़े में ई-मेल और एसएमएस के अनुस्मारक भेजे जाएंगे।
- 10.1.10 अधिसूचित ऋणदाता एजेंसी द्वारा आवधिक ऋण स्वीकृत किए जाने पश्चात भी आवेदन किया जा सकता है। ऐसे मामले में आवेदक, आवधिक ऋण स्वीकृत किए जाने के अधिकतम छह महीने के भीतर आई-टीयूएफएस में यूआईडी के लिए सीधे आवेदन करेगा।
- 10.1.11 आवेदक अपने ई-मेल, मोबाइल नं. और पैन के विवरण के साथ आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में पंजीकरण करेगा। वह सिस्टम में यथाअपेक्षित सूचना भरेगा और अपने डिजिटल हस्ताक्षर/आधार आधारित ई-हस्ताक्षर करेगा।
- 10.1.12 आवेदन, परियोजना और ऋण के विवरण के सत्यापन के लिए संबंधित ऋणदाता एजेंसी को भेजा जाएगा। ऋणदाता एजेंसी अपने पास उपलब्ध ऋण दस्तावेजों से आवेदन का सत्यापन करेगी; अंतिम ऋण स्वीकृति आदेश की प्रति अपलोड करेगा और ऋणदाता एजेंसी के प्राधिकृत अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर के साथ सत्यापन को हस्ताक्षरित करेगी। ऋणदाता एजेंसी आवेदन प्राप्ति के दो महीने के भीतर प्रक्रिया को पूरा करने का प्रयास करेगी।
- 10.1.13 यदि आवेदक और ऋणदाता एजेंसी द्वारा दी गई सूचना में कोई विसंगति पाई जाती है तो आवेदक से संगत साक्ष्य प्राप्त करके वस्त्र आयुक्त के कार्यालय द्वारा उसका समाधान किया जाएगा और यदि आवश्यकता होगी तो ऋणदाता एजेंसी को सूचित किया जाएगा।
- 10.1.14 ऋणदाता एजेंसी द्वारा सफलतापूर्वक सत्यापित आवेदन, वस्त्र आयुक्त के इन-बॉक्स में जाएंगे और स्वतः यूआईडी तैयार हो जाएगी। कंपनी को उनके पंजीकृत ई-मेल और मोबाइल नं. पर यूआईडी के बारे में सूचित किया जाएगा।
- 10.1.15 यूआईडी, अनुमानित सब्सिडी के लिए अनंतिम अनुमोदन होगा। संयुक्त निरीक्षण के परिणाम के आधार पर वास्तविक सब्सिडी का निर्णय लिया जाएगा जिसकी क्रियाविधि का विस्तृत विवरण इसके बाद वाले पैराग्राफ में दिया गया है।
- 10.1.16 जो आवेदन, ऋणदाता एजेंसी के स्तर पर सत्यापन जांच अथवा डाटा की गुणवत्ता जांच में असफल हो जाते हैं, उन्हें निरस्त कर दिया जाएगा। कंपनी के पास नए सिरे से आवेदन करने का विकल्प होगा। इस स्तर पर कोई शिकायत होने पर उसे आई-टीयूएफएस में सृजित शिकायत मोड्यूल में वस्त्र आयुक्त के साथ उठाया जा सकता है। वस्त्र आयुक्त, शिकायत प्राप्त होने के तीस दिन के भीतर उसका निपटान करेगा।
- 10.1.17 यह सुनिश्चित करने के लिए कि सिस्टम में डाटा की गलती न हो, आई-टीयूएफएस सॉफ्टवेयर में स्ट्रांग मेकर-चैकर, करेक्टर कंट्रोल और अन्य आंतरिक कंट्रोल की व्यवस्था करेगा। तथापि, आवेदक को यह सुनिश्चित करना होगा कि डाटा त्रुटि रहित है और सभी अपेक्षित दस्तावेज ठीक ढंग से अपलोड किए गए हैं। आवेदनों में त्रुटि होने से आवेदन को निरस्त कर दिया जाएगा।
- 10.2 मशीनरी की स्थापना:
- 10.2.1 सब्सिडी केवल उन मशीनों के लिए उपलब्ध होगी जो इस योजना के अंतर्गत यथानिर्दिष्ट प्रौद्योगिकी के मानदंडों को पूरा करती हों।
- 10.2.2 केवल नई मशीनों की स्थापना की जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पुरानी मशीन को अनुमति नहीं दी जाएगी। मशीन, सीधे ही मूल उपकरण विनिर्माता (ओईएम) अथवा उसके प्राधिकृत एजेंट/आपूर्तिकर्ता से खरीदी जाएगी। प्राधिकृत एजेंट/आपूर्तिकर्ता के मामले में बीजक के साथ एक दस्तावेज अपेक्षित होगा जिसमें यह दर्शाया गया हो कि वह एजेंट/आपूर्तिकर्ता विनिर्माता द्वारा प्राधिकृत है।
- 10.2.3 मशीन का नाम और उसका क्रमांक, वाणिज्यिक बीजक/लैंडिंग बिल/एयरवे बिल/बिल ऑफ एंट्री पर स्पष्ट रूप से लिखा होना चाहिए।
- 10.2.4 मशीनरी का मॉडल नं. और क्रमांक मशीन पर स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट करना होगा।
- 10.2.5 यूआईडी के अंतर्गत कवर की गई मशीनरी की स्थापना और शुरुआत आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से एक साल के अंदर करनी होगी। एक साल से आगे विस्तार की अनुमति दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत करने पर ही दी जा सकती है कि विनिर्दिष्ट समय-सीमा अर्थात् आवधिक ऋण की स्वीकृति की तिथि से एक साल के अंदर मशीनरी खरीदने के ऑर्डर कर दिए गए थे।
- 10.2.6 यदि मशीनरी प्रौद्योगिकी विशिष्टता को पूरा करती है लेकिन विनिर्माता को सांकेतिक सूची में शामिल नहीं की गई है तो जेआईटी के लिए अनुरोध पर विचार किया जाएगा। ऐसे मामले में मशीनरी की पात्रता की जांच के लिए सूची में शामिल किए जाने के लिए वस्त्र आयुक्त का कार्यालय के लिए अलर्ट सृजित किया जाएगा और इसे तकनीकी समिति की आगामी मासिक बैठक में सूचीबद्ध किया जाएगा अथवा अस्वीकृत किया जाएगा। यह प्रक्रिया टीएमसी के अनुमोदन के साथ-साथ 45 दिनों के भीतर पूरी हो जानी चाहिए।

- 10.2.7 समय पर जेआईटी को फाइल करने के लिए कंपनी को हर पखवाड़े में अनुस्मारक मेल और एसएमएस भेजा जाएगा। यदि विनिर्दिष्ट समय-सीमा के भीतर जेआईटी के लिए अनुरोध नहीं किया गया है अथवा विस्तार के लिए कोई अनुरोध नहीं किया गया है तो समय-सीमा की समाप्ति से पूर्व 20 दिन के भीतर कंपनी को एक प्रणाली जनित चेतावनी मेल और एसएमएस भेजा जाएगा कि जेआईटी आवेदन समय-सीमा की समाप्ति के अंदर दायर नहीं करने पर यूआईडी रद्द कर दी जाएगी। यदि संयुक्त निरीक्षण के लिए समय-सीमा में अनुरोध नहीं किया गया है तो यूआईडी स्वतः रद्द हो जाएगी और इस संबंध में अभ्यावेदन पर आगे कोई विचार नहीं किया जाएगा।
- 10.3 कंपनी के संयुक्त निरीक्षण के लिए आवेदन दायर करने की प्रक्रिया:
- 10.3.1 मशीनरी की स्थापना के पश्चात कंपनी, संयुक्त निरीक्षण के लिए ऑनलाइन आवेदन दायर करेगी।
- 10.3.2 सिस्टम, कंपनी की यूआईडी से सभी आवश्यक सूचना लेगा। आवेदक, जेआईटी के लिए आवेदन करते समय प्रत्येक मशीनरी के लिए निम्नलिखित सूचना प्रदान करेगा:
- i. मशीनरी का निर्माण और मॉडल
 - ii. मशीनरी की क्रमांक
 - iii. मशीनरी की मूलभूत लागत
 - iv. सहायक कल-पुर्जों की मूलभूत लागत
 - v. मशीनरी पर चुकाया गया सीमा शुल्क
 - vi. खरीद की तिथि
 - vii. खरीद के साक्ष्य (भुगतान रसीद/अंतिम बीजक अपलोड करें)
 - viii. निर्माता देश (आयातित मशीनों के मामले में)
 - ix. निर्यातक देश
 - x. बिल ऑफ लेडिंग की तिथि (बिल ऑफ लेडिंग अपलोड करें)
 - xi. बिल ऑफ एंट्री की तिथि (बिल ऑफ एंट्री अपलोड करें)
 - xii. मशीनरी शुरूआत की तिथि
 - xiii. परियोजना में किया गया निवेश
 - xiv. परियोजना में कार्यरत व्यक्तियों की संख्या
 - xv. भुगतान संबंधी विवरण दर्शाने वाला बैंक विवरण
- 10.3.3 जेआईटी आवेदन के समय मशीनरी आंकड़े को जोड़ने अथवा घटाने की अनुमति दी जाएगी।
- 10.3.4 कंपनी, जेआईटी के अनुमोदन के पश्चात इकाई को निधियों के अंतरण हेतु इस स्तर पर सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (पीएफएमएस) पंजीकरण के लिए प्रासंगिक सूचना भी प्रदान करेगी।
- 10.3.5 सिस्टम में जैसे ही उपर्युक्त सूचना प्रदान की जाती है, सॉफ्टवेयर, प्रत्येक मशीन के लिए एक एमआईसी कोड सृजित करेगा। एमआईसी कोड को मशीन पर उकेरा जाएगा और वास्तविक निरीक्षण के दौरान संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा इसे सत्यापित किया जाएगा।
- 10.3.6 एमआईसी के माध्यम से सेगमेंट, मशीन के निर्माता देश, राज्य/प्रांत कोड, जहां मशीन स्थापित की गई है, विनिर्माता कोड, अधिकृत एजेंट कोड, वाणिज्यिक बीजक नम्बर, बिल ऑफ एंट्री, बिल ऑफ लेडिंग, मशीन क्रमांक आदि से संबंधित विवरण का पता लगाया जा सकता है।

- 10.3.7 आवेदक को अपने डिजिटल हस्ताक्षर से जेआईटी आवेदन पर हस्ताक्षर करने होंगे। अनुरोध, वस्त्र आयुक्त के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को भेजा जाएगा। वस्त्र आयुक्त, ऋणदाता एजेंसियों, उद्योग और वस्त्र अनुसंधान संघ के सदस्यों से वस्त्र आयुक्त के क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत स्थापना के वास्तविक सत्यापन और मशीनरियों की शुरुआत के लिए संयुक्त निरीक्षण दलों (जेआईटी) का गठन करेगा और कंपनी के लिए पात्र सब्सिडी की धनराशि की सिफारिश करेगा। जेआईटी को संयुक्त निरीक्षण, आवेदन के 88 दिनों के भीतर वास्तविक निरीक्षण पूरा करना है।
- 10.4 जेआईटी रिपोर्ट को प्रस्तुत करना
- 10.4.1 क्षेत्रीय कार्यालय, संयुक्त निरीक्षण दल की रिपोर्ट को उसी दिन अथवा अधिकतम अगले दिन आई-टप्स सॉफ्टवेयर में जियो-टैग और समय वाली मुहर के फोटोग्राफ के साथ प्रदान करेगा। क्षेत्रीय कार्यालय, उसके द्वारा विधिवत रूप से सत्यापित बीजक की अंतिम प्रतिलिपि भी अपलोड करेगा और अपने डिजिटल हस्ताक्षर से हस्ताक्षर कर सत्यापन करेगा।
- 10.4.2 कंपनी, अपनी जेआईटी रिपोर्ट को देखेगी। इकाई, आई-टप्स में सृजित मॉड्यूल में जेआईटी रिपोर्ट से असहमति के मामले में 15 दिन के भीतर वस्त्र आयुक्त को अभ्यावेदन दे सकती है। वस्त्र आयुक्त को 30 दिन के भीतर उसके अभ्यावेदन का निपटान करना होगा।
- 10.4.3 वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा ऑनलाइन जेआईटी रिपोर्ट दर्ज करने के अधिकतम 25 कार्य दिवसों के भीतर सब्सिडी संबंधी दावों का अनुमोदन करेगा। सब्सिडी अनुमोदन के लिए विनिर्माता अथवा उसका प्राधिकृत एजेंट/आपूर्तिकर्ता का सूचीबद्ध होना अनिवार्य होगा।
- 10.5 कंपनी के खाते में पात्र सब्सिडी जारी करना:
- 10.5.1 वस्त्र आयुक्त के अनुमोदन के पश्चात आई-टप्स में एक स्वचालित चालान सृजित होगा।
- 10.5.2 वस्त्र आयुक्त, मंत्रालय को वह चालान भेजेगा और मंत्रालय, मंत्रालय में चालान की प्राप्ति के 15 कार्य दिवसों के भीतर कंपनी के खाते में सब्सिडी जारी करेगा।
- 10.5.3 एटप्स के अंतर्गत आवेदक द्वारा किसी ऋणदाता एजेंसी से ऋण लेने के मामले में पूरी धनराशि जारी की जाएगी। यदि आवेदक ने आवधिक की डाउन सेलिंग ऋण अथवा कन्सोर्टियम फाइनेन्स की सुविधा प्राप्त की है तो सब्सिडी की राशि यथा मूल्य आधार पर ऋणकर्ता के खाते में जमा की जाएगी।
11. मॉनीटरिंग तंत्र:
- योजना पर नियंत्रण दो स्तरीय मॉनीटरिंग तंत्र अर्थात् तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) और अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी) द्वारा किया जाएगा।
- 11.1 तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी):
- वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में एक तकनीकी सलाहकार एवं मॉनीटरिंग समिति (टीएएमसी) का गठन किया जाएगा जिसमें विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करते तकनीकी विशेषज्ञ और उद्योग शामिल होंगे। टीएएमसी का गठन एवं कार्य अनुबंध-घ पर संलग्न है।
- 11.2 टीएएमसी, योजना की प्रगति पर निगरानी रखेगी तथा योजना के क्रियान्वयन के सभी पहलुओं पर आईएमएससी को अवगत कराएगी और सलाह देगी।
- 11.3 वस्त्र आयुक्त के कार्यालय और मंत्रालय द्वारा नियमित आधार पर परियोजना के प्रचालन के दौरान मशीनरी की नमूना जांच की जाएगी (एमएसएमई के लिए न्यूनतम विनिर्दिष्ट अवधि 3 वर्ष और गैर-एमएसएमई इकाइयों के लिए 5 वर्ष है)। कार्यभार के आधार पर इस प्रयोजन के लिए मंत्रालय के अनुमोदन से एक तृतीय पक्ष इंजीनियरिंग परामर्शदाता (दाताओं) को भी नियुक्त किया जा सकता है।
- 11.4 अंतर-मंत्रालयी संचालन समिति (आईएमएससी):
- वस्त्र मंत्री की अध्यक्षता में संबंधित मंत्रालयों, नीति आयोग, ऋणदाता एजेंसियों, वस्त्र उद्योग के संघों आदि के प्रतिनिधियों से आईएमएससी का गठन किया जाएगा। आईएमएससी, आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति के अनुमोदन के अनुरूप योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु मॉनीटरिंग और दिशानिर्देश तैयार करने के लिए उत्तरदायी होगी। आईएमएससी का गठन तथा कार्य अनुबंध-ड पर दिया गया है।

- 11.5 आईएमएससी योजना की प्रगति की अर्द्धवार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसका प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करेगी।
12. यूआईडी के निरस्तीकरण हेतु प्रावधान:
- 12.1 इस योजना के अंतर्गत उन मामलों में जहां आवेदक संयुक्त निरीक्षण दल द्वारा भौतिक सत्यापन करने के लिए आवधिक ऋण स्वीकृत किए जाने की तारीख से एक वर्ष के भीतर मशीन की स्थापना की सूचना देने में विफल रहता है, तो जारी की गई यूआईडी निरस्त कर दी जाएगी, किंतु यदि ऐसे पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण के आधार पर उसे वस्त्र आयुक्त द्वारा एक वर्ष से अधिक समय के विस्तार की अनुमति दे दी गई हो कि मशीनरी के ऑर्डर निर्धारित अवधि के भीतर कर दिए गए थे तथापि उद्यमी के नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के कारण उसकी स्थापना और शुरुआत नहीं हो सकी, तो यूआईडी को निरस्त नहीं किया जाएगा।
- 12.2 यदि कंपनी किसी कारण से योजना के अंतर्गत सब्सिडी का लाभ नहीं लेने का निर्णय करती है तो वह आई-टप्स सॉफ्टवेयर में यूआईडी के निरस्तीकरण के लिए अनुरोध कर सकती है।
13. शिकायत निवारण प्रणाली:
- 13.1 आई-टप्स में एक शिकायत निवारण मॉड्यूल है। योजना के क्रियान्वयन के कारण उत्पन्न हुई शिकायतें वस्त्र आयुक्त द्वारा 30 दिन के भीतर हल की जाएंगी।
14. दिशानिर्देशों में संशोधन:
- वित्तीय मामलों से जुड़े इन दिशानिर्देशों में कोई भी संशोधन, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) के पूर्व अनुमोदन के द्वारा ही किया जाएगा। वित्तीय मामलों को छोड़कर अन्य मामलों से संबंधित संशोधन, आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किए जा सकते हैं और तात्कालिकता के मामले में आईएमएससी की अगली बैठक में पुष्टि के अध्यक्ष अध्याक्ष के अनुमोदन से संशोधन किया जा सकता है।
15. दिनांक 29 फरवरी, 2016 के समसंख्यक आदेश द्वारा जारी किए गए संकल्प को इस संशोधित संकल्प द्वारा अधिक्रमण किया जाएगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को सामान्य सूचना हेतु भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रतियां संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को प्रेषित की जाएं।

संजय शरन

संयुक्त सचिव

अनुबंध – क

एटीयूएफएस के अंतर्गत ऋणदाता एजेंसी को शामिल करने हेतु प्रपत्र

(त किया जाना है को प्रस्तुत आयुक्तम से वस्त्रएटीयूएफएस सॉफ्टवेयर के माध्यम-आई)

| | | |
|----|-------------------------------------|--|
| 1. | बैंक का नाम | |
| 2. | पता | |
| 3. | संपर्क किए जाने वाले व्यक्ति का नाम | |
| 4. | फोन नंबर | |
| 5. | मोबाइल नंबर | |
| 6. | ई-मेल आईडी | |
| 7. | फैक्स नंबर | |

हस्ताक्षर

दिनांक :

सील के साथ नाम एवं पदनाम

संलग्नकों का विवरण:

1. बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 के अंतर्गत आरबीआई द्वारा जारी बैंकिंग लाइसेंस की प्रति
2. आरबीआई अधिनियम, 1934 की दूसरी अनुसूची में शामिल किए जाने हेतु आरबीआई द्वारा जारी पत्र की प्रति
3. मल्टी स्टेट को-ऑपरेटिव एक्ट, यदि लागू हो तो, के अंतर्गत पंजीकरण हेतु भारत सरकार द्वारा जारी प्रति
4. पैन/टैन संख्या की प्रति
5. पिछले तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र की प्रति
6. अन्य संबंधित जानकारी, यदि कोई हो।

अनुबंध-ख**एकाधिक वित्तपोषण न होने का वचनपत्र-****(कंपनी के पत्र शीर्ष पर)****दिनांक :**

_____ एतद्वारा यह प्रमाणित करती है कि किसी मशीनरी अथवा उसके किसी (कंपनी का नाम)भाग, जिसके लिए एटीयूएफएस के अंतर्गत लाभों के लिए दावा किया गया है, हेतु इस बैंक तथा अथवा/ **किसी अन्य बैंक** य वित्ती/एजेंसियों/ऋणदाता एजेंसी/(बैंकों) नहीं किया है। नों से एक बार से अधिक ऋण प्राप्त संस्था

शुरू की गई सभी परियोजनाओं तथा प्राप्त किए गए ऋणों, जहां हमारे द्वारा टीयूएफएस के अंतर्गत लाभ प्राप्त किए गए हैं, का विवरण नीचे दिया गया है :

| क.सं. | परियोजना का नाम | परियोजना लागत | प्राप्त किए गए ऋण | ऋणदाता बैंक/वित्तीय संस्थान/ऋणदाता एजेंसी |
|-------|-----------------|---------------|-------------------|---|
| | | | | |
| | | | | |
| कुल | | | | |

हम यह वचन भी देते हैं कि उल्लिखित तथ्यों में किसी प्रकार की गलती पाए जाने पर लगाए गए दण्डात्मक ब्याज सहित संपूर्ण सब्सिडी की सरकार को प्रतिपूर्ति की जाएगी।

कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के हस्ताक्षर

नाम तथा पदनाम

- * टीयूएफएस (प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना) का तात्पर्य टीयूएफएस, एमटीयूएफएस, आरटीयूएफएस, आरआरटीयूएफएस एवं एटीयूएफएस है।

टीयूएफएस संदर्भ संख्या _____

अनुबंध-ग

कंपनी के प्रबंधन का विलय अधिग्रहण/

| | पुराना प्रबंधन | नया प्रबंधन |
|---------------|----------------|-------------|
| कंपनी का नाम | | |
| सीआईएन संख्या | | |

| प्रवर्तकों का विवरण | | | | | | | | |
|-------------------------------|-----|---------|------------|-------------|-----|---------|------------|-------------|
| | नाम | पैन सं. | डीआईएन सं. | आधार संख्या | नाम | पैन सं. | डीआईएन सं. | आधार संख्या |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| ऋण खाता संख्या | | | | | | | | |
| ऋणदाता एजेंसी का नाम | | | | | | | | |
| ऋणदाता एजेंसी का आईएफएससी कोड | | | | | | | | |

अनुबंध-घ

टीएमसी का गठन

| | | |
|-----|---|---------|
| 1. | वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई | अध्यक्ष |
| 2. | निदेशक (एटीयूएफएस), वस्त्र मंत्रालय | सदस्य |
| 3. | पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता | सदस्य |
| 4. | औद्योगिक सलाहकार, भारी उद्योग विभाग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 5. | अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ, नई दिल्ली | सदस्य |
| 6. | अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (एमएफआईडब्ल्यू), मुंबई | |
| 7. | अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडियन आर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री, (आईएफआईएसडब्ल्यू), सूरत | सदस्य |
| 8. | अध्यक्ष, भारतीय स्पिनर्स संघ (आईएसए), मुंबई | सदस्य |
| 9. | अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स संघ (एसआईएसपीए), कोयम्बटूर | सदस्य |
| 10. | अध्यक्ष, लुधियाना निटवियर क्लब, लुधियाना | सदस्य |
| 11. | अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माता संघ (टीएमएमआई), मुंबई | सदस्य |
| 12. | अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए), कोलकाता | सदस्य |
| 13. | अध्यक्ष, क्लोदिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (सीएमआई), मुंबई | सदस्य |
| 14. | अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (डिक्सिलपे), मुंबई | सदस्य |
| 15. | अध्यक्ष, कॉटन टेक्सटाइल्स एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (प्रोसिलटेक्स), मुंबई | सदस्य |
| 16. | अध्यक्ष, अपैरल निर्यात संवर्धन परिषद (एईपीसी), गुडगांव | सदस्य |
| 17. | अध्यक्ष, सिंथेटिक एवं रेयान टेक्सटाइल्स संवर्धन परिषद, मुंबई | सदस्य |

| | | |
|-----|--|------------|
| 18. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, आईडीबीआई बैंक, मुंबई | सदस्य |
| 19. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी)), लखनऊ | सदस्य |
| 20. | अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल संघ, कोयम्बटूर | सदस्य |
| 21. | अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई | सदस्य |
| 22. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम, नई दिल्ली | सदस्य |
| 23. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई | सदस्य |
| 24. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई | सदस्य |
| 25. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई | सदस्य |
| 26. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, एनसीडीसी, नई दिल्ली | सदस्य |
| 27. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुंबई | सदस्य |
| 28. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, इंडियन ओवरसीज बैंक, मुंबई | सदस्य |
| 29. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई | सदस्य |
| 30. | प्रभारी, टीयूएफएस प्रकोष्ठ, पंजाब नेशनल बैंक, मुंबई | सदस्य |
| 31. | निदेशक, बाम्बे टेक्सटाइल रिसर्च एसोसिएशन, मुंबई | सदस्य |
| 32. | एटीयूएफएस, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई के प्रभारी अपर/संयुक्त वस्त्र आयुक्त | सदस्य सचिव |

2. टीएएमसी, क्षेत्र-वार प्रगति के साथ-साथ योजना की प्रगति की समीक्षा तथा निगरानी करेगी और मंत्रालय तथा आईएमएससी को त्रैमासिक आधार पर सूचित करेगी।

3. टीएएमसी, पात्र बेंचमार्क वाली मशीनरी को हर वर्ष 1 अप्रैल को अद्यतन तथा विनिर्दिष्ट करेगी।

अनुबंध-ड

आईएमएससी का गठन

| | | |
|-----|--|-----------|
| 1. | केंद्रीय वस्त्र मंत्री | अध्यक्ष |
| 2. | सचिव, वस्त्र मंत्रालय | उपाध्यक्ष |
| 3. | सचिव, व्यय विभाग | सदस्य |
| 4. | सचिव, वित्तीय सेवाएं विभाग | सदस्य |
| 5. | सचिव, वाणिज्य विभाग | सदस्य |
| 6. | सचिव, औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग | सदस्य |
| 7. | सचिव, भारी उद्योग विभाग | सदस्य |
| 8. | सचिव, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय | सदस्य |
| 9. | उप-गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक | सदस्य |
| 10. | अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार, वस्त्र मंत्रालय | सदस्य |
| 11. | वस्त्र आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, मुंबई | सदस्य |
| 12. | पटसन आयुक्त, वस्त्र मंत्रालय, कोलकाता | सदस्य |

| | | |
|-----|---|------------|
| 13. | विकास आयुक्त (हथकरघा), नई दिल्ली | सदस्य |
| 14. | सलाहकार, (वस्त्र प्रभारी), नीति आयोग, नई दिल्ली | सदस्य |
| 15. | सदस्य सचिव, केंद्रीय रेशम बोर्ड, बेंगलुरु | सदस्य |
| 16. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईडीबीआई | सदस्य |
| 17. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, सिडबी | सदस्य |
| 18. | अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, आईएफसीआई | सदस्य |
| 19. | अध्यक्ष, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया | सदस्य |
| 20. | अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र मशीनरी विनिर्माता संघ (टीएमएमएआई), मुंबई | सदस्य |
| 21. | अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (सीआईटीआई), नई दिल्ली | सदस्य |
| 22. | अध्यक्ष, फेडरेशन ऑफ इंडिया आर्ट सिल्क विविंग इंडस्ट्री, सूरत | सदस्य |
| 23. | अध्यक्ष, भारतीय ऊनी मिल परिसंघ (आईडब्ल्यूएमएफ), मुंबई | सदस्य |
| 24. | अध्यक्ष, विद्युतकरघा विकास एवं निर्यात संवर्धन परिषद (पेडिक्सिल), मुंबई | सदस्य |
| 25. | अध्यक्ष, भारतीय पटसन मिल संघ (आईजेएमए), कोलकाता | सदस्य |
| 26. | अध्यक्ष, क्लोदिंग मैनुफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया, मुंबई | सदस्य |
| 27. | अध्यक्ष, भारतीय तकनीकी वस्त्र संघ (आईटीटीए), मुंबई | सदस्य |
| 28. | अध्यक्ष, दक्षिण भारत स्पिनर्स संघ, कोयम्बटूर | सदस्य |
| 29. | अध्यक्ष, दक्षिण भारत मिल संघ, कोयम्बटूर | सदस्य |
| 30. | अपर/संयुक्त सचिव (एटीयूएफएस प्रभारी) | सदस्य सचिव |

.2 आईएमएससी, सीसीईए के अनुमोदन के अनुसार योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशानिर्देशों को तैयार करने और उनकी मॉनीटरिंग के लिए उत्तरदायी होगी। आईएमएससी, योजना की प्रगति की अर्द्ध वार्षिक आधार पर समीक्षा करेगी तथा इसके प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी।

.3 वित्तीय मामलों के अतिरिक्त अन्य मामलों के संबंध में योजना में कोई भी संशोधन आईएमएससी के अनुमोदन द्वारा किया जा सकता है।

MINISTRY OF HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

(DEPARTMENT OF HIGHER EDUCATION)

[U.3(A) SECTION]

New Delhi, the 8th August, 2018

No. F.9-15/93-U.3(Pt.1).—Whereas, the Central Government is empowered under Section 3 of the University Grants Commission (UGC) Act, 1956 to declare, on the advice of the UGC, an Institution of higher learning as deemed to be University.

2. **And whereas**, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government vide its Notification No.9-15/93-U.3 dated 29.09.1994, on the advice of UGC, had declared Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Madras as an Institution deemed to be University with certain conditions.

3. **And whereas**, Registrar, Sri Ramachandra Medical College and Research Institute, Chennai on 25.11.2017 had submitted a request for change of name of the Institution from “Sri Ramachandra Medical College & Research Institute” to “Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research”.

4. **And whereas**, the Ministry of Human Resource Development, vide its letter No. 9-15/93-U.3(Pt.1) dated 16.02.2018, had conveyed its in-principle approval for change of the name of the Institute subject to fulfillment of the following conditions:

- i. A specific and exclusive Society / Trust / Campany shall be registered in the revised name.
- ii. All the assets (moveable & immoveable) shall be legally transferred in the newly proposed name.
- iii. The Corpus fund to be transferred in the new name.
- iv. The Institution shall align its MoA / Rules in accordance with the UGC (Institutions Deemed to be Universities) Regulations, 2016.

5. **And further whereas**, the Institution submitted the compliance report with regard to the above mentioned conditions which were verified by the University Grants Commission.

6. **Now, therefore**, in exercise of the powers conferred under Section 3 of the UGC Act, 1956, the Central Government, on the advice of the UGC, do hereby change the name of “**Sri Ramachandra Medical College & Research Institute**” to “**Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research**” w.e.f. the issuance of this Notification. Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Porur, Chennai shall not use the word ‘University’ suffixed to its name but may mention the word “deemed to be university” within parenthesis suffixed thereto.

7. The all other conditions mentioned in the earlier Notification(s) of this Ministry as well as the Norms / Regulations of UGC and Statutory Council(s) concerned, issued from time to time, shall continue to be adhered by Sri Ramachandra Institute of Higher Education and Research, Porur, Chennai

ISHITA ROY

Joint Secretary

MINISTRY OF TEXTILES

New Delhi, the 2nd August, 2018

REVISED RESOLUTION

In supersession with the GR of even number dated 29th February 2016

No.6/5/2015-TUFS.—The Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS) has been notified by the Ministry of Textiles vide Resolution of even number dated 13.01.2016. In accordance to the said Resolution, the

Guidelines of ATUFS i.e. financial and operational parameters and implementation mechanism for ATUFS during its implementation period from 13.01.2016 to 31.03.2022 are laid down as under:

1. Objective:

- 1.1. In order to promote ease of doing business in the country and achieve the vision of generating employment and promoting exports through “Make in India” with “Zero effect and Zero defect” in manufacturing, it has been decided that the Government would provide credit linked Capital Investment Subsidy (CIS) under Amended Technology Upgradation Fund Scheme (ATUFS).
- 1.2. The scheme would facilitate augmenting of investment, productivity, quality, employment, exports along with import substitution in the textile industry. It will also indirectly promote investment in textile machinery (having benchmarked technology) manufacturing.

2. Definitions under the Scheme

- 2.1. Technology Upgradation means induction of new machinery by an entity engaged in the textile industry with state-of-the-art technology as specified annually by the Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC). Technology lower than the specified one will not be treated as Technology Upgradation.
- 2.2. Capital Investment Subsidy (CIS) means the subsidy at prescribed rate on credit linked Capital Investment to an entity engaged in textile sector on technology upgradation which will be determined on the basic cost of the specified machinery after its installation and commissioning.
- 2.3. Basic cost means cost of machinery excluding taxes, duties and any other charges.
 - 2.4 Entity means the following engaged in manufacturing of textiles products:
 - i. Companies registered under the Companies Act, 1956 as amended from time to time or
 - ii. Limited Liability Partnership Firms registered under LLP Act 2008 as amended from time to time or
 - iii. Medium and Small Enterprises registered under MSME Act as amended from time to time or
 - iv. Companies having Industrial Entrepreneur Memorandum (IEM) with the Department of Industrial Policy and Promotion or
 - v. The Entities registered with the concerned Directorates of the State Government
- 2.5. Lending Agency includes all Public Sector Banks, State Financial Corporation’s (SFCs), State Industrial Development Corporations (SIDCs), Scheduled Banks, Cooperative Banks and NBFCs registered with RBI and notified by the TAMC.
- 2.6. Garment/Apparel/Made-ups means wearable or non-wearable stitched fabrics at least two sides of which are stitched using sewing machinery.
- 2.7. Technical Textiles means textile materials and products used primarily for their technical performance and functional properties and it includes Agrotex Meditex, Mobiltex ,Packtex, Sportex, Buildtex, Clothtex, Hometex, Protex, Geotex, Oekotex and Indutex etc
- 2.8. Unique Identification number (UID) means provisional approval for estimated Capital investment Subsidy (CIS) based on the tentative estimates of specified machineries for technology upgradation.

3. Eligibility for Capital Investment Subsidy

- 3.1. Capital Investment Subsidy (CIS) will be available only to the entities for investment on technology upgradation in the following segments:
 - (a) Weaving, Weaving Preparatory and knitting
 - (b) Processing of fibres, yarns, fabrics, garments and made-ups

- (c) Technical textiles
 - (d) Garment / made-up manufacturing
 - (e) Handloom Sector
 - (f) Silk Sector
 - (g) Jute Sector
- 3.2. Specifications of technology for the machinery for all the above segments would be prescribed annually in advance by the TAMC effective from 1st April of the year.
- 3.3. Machinery purchased directly from the machine manufacturers or their authorized agents/suppliers will be eligible for capital subsidy under the scheme.
- 3.4. For the convenience of the industry, the TAMC shall also get an indicative list of manufacturers of machineries conforming to the specifications of technology prescribed under Para 3.2, with the assistance of a Technical Committee comprising of the members from the Industry and experts and headed by the senior most technical officer in the O/o the Textile Commissioner. Textile Commissioner will constitute this Committee. The indicative list will be kept on the website for access by general public and offering comments/suggestion which will be finally approved by the TAMC. This Committee will meet on monthly basis to update the list of such machineries and manufacturers.
- 3.5. Machinery with technology levels lower than those specified in para 3.2 above will not be eligible for subsidy under the scheme. However, the list of manufacturers and machinery prepared under para 3.3 above will only be suggestive and shall not be treated as exhaustive or complete. Industry will be at liberty to purchase machinery of their choice conforming to the specified technology parameters. In such cases, the Technical Committee mentioned in para 3.4 above will verify those manufacturers and machinery and if found suitable, propose their inclusion in the indicative list of manufacturers by the TAMC.
- 3.6. The JIT application would be processed on matching the technology specifications as prescribed under para 3.2 but the subsidy disbursement would be done on the basis of inclusion of the manufacturer and machinery in the indicative list prepared and updated under 3.3 and 3.4.
- 3.7. Second hand Machinery will not be eligible for subsidy under the scheme.
- 3.8. Accessories / attachments / sample machines / spares received along with the machinery or procured from other manufacturers enlisted in the indicative list upto a value of 20% of the basic cost of the machinery will also be eligible for subsidy.
- 3.9. Machinery eligible for one segment is eligible for other segment(s)/ activity (ies) also unless its eligibility is specifically restricted for a particular segment/ activity.
- 3.10. Except in case of merger, acquisition, amalgamation or takeover of the entity, the plant & machinery purchased with the subsidy under TUFS shall not be disposed off before 10 years of date of purchase without prior approval of Textile Commissioner.

4. Norms for subsidy:

- 4.1. Every eligible individual entity (not the unit) will be entitled for reimbursement of Capital Investment Subsidy (CIS) under this scheme, as per the following rates:

| Sl. No. | Segment | Rate of Capital Investment Subsidy (CIS) |
|---------|---|---|
| 1. | Garmenting, Technical Textiles | 15% subject to an upper limit of Rs 30 crores |
| 2. | Weaving for brand new Shuttle-less Looms (including weaving preparatory and knitting), Processing, Jute, Silk and Handloom. | 10% subject to an upper limit of Rs 20 crores |

| | | |
|------|--|---|
| 3(a) | Composite unit /Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is more than 50% of the eligible project cost. | 15% subject to an upper limit of Rs 30 crores |
| 3(b) | Composite unit/ Multiple Segments - If the eligible capital investment in respect of Garmenting and Technical Textiles category is less than 50% of the eligible project cost. | 10% subject to an upper limit of Rs 20 crores |

- 4.2. In case the entity had availed subsidy earlier under RRTUFS, it will be eligible to the extent of balance subsidy for new or existing units within the overall ceiling fixed for an individual entity.
- 4.3. The scheme is credit linked. The capital investment subsidy (CIS) shall be available to the entity on availing term loan from a notified lending agency with minimum 50% of the total eligible machinery cost under the project.
- 4.4. In order to ensure that the availing of subsidy remains within the prescribed ceiling, the entity will be required to furnish a declaration of the subsidy availed by it under the RRTUFS and the ATUFS.
- 4.5. CIS will be released to the entity in full in one go on eligible investment after satisfactory installation/commissioning and commencement of production.

5. Norms for the term loan for availing CIS:

- 5.1. Term loan shall be sanctioned by a notified lending Agency. The lending agencies covered under RRTUFS as per Resolution No. 6/19/2013-TUFS dated 04.10.2013 are automatically covered under this scheme and new lending agency (ies) would require to submit their application in the prescribed format as per **Annexure-A** to the Textile Commissioner, Mumbai through i-TUFS software in order to notify the lending agency under ATUFS.
- 5.2. The scheme is credit linked. The capital investment subsidy (CIS) shall be available to the entity on availing term loan from a notified lending agency with minimum 50% of the total eligible machinery cost under the project.
- 5.3. No multiple finance for a project is allowed under this scheme. The beneficiary will be required to give an undertaking in this regard in the prescribed format as per **Annexure B**.
- 5.4. The minimum repayment period of the term loan sanctioned for availing the benefit of the scheme shall not be for less than three years including moratorium period for MSME units and not less than 5 years for other categories.
- 5.5. Unit for which loan has been taken shall function atleast during the repayment period of term loan specified above.
- 5.6. Foreign Currency Loan: Foreign Currency Loan availed from overseas branch of the Indian Bank/ foreign bank having Indian branch will be eligible for benefits under this scheme. However, the loan account should be operational from the Indian branch also so as to make it possible to transfer the subsidy amount in Indian Rupee into the account of the applicant in the Indian branch. Conversion of Rupee Term Loan (RTL) into Foreign Currency Loan (FCL) and *vice-versa* is permitted.
- 5.7. The outstanding principal loan amount can be transferred from one lending agency to another lending agency subject to the condition that portfolio remains unchanged.

6. Sanction date:

- 6.1 The sanction date shall be the date of the letter of the lending agency through which sanction of the loan was communicated to the entity.
- 6.2. In case the term loan is sanctioned by a lending agency and thereafter the lending agency distributes / down-sells the term loan to other lending agency (ies) or has sanctioned term loan under consortium finance, the date of sanction of the term loan shall be as under:
- (i) In case of down-selling the term loan, the date of loan sanction letter of the first lending agency, which has sanctioned the term loan initially, shall be relevant date

- (ii) In case of consortium finance, date of loan sanction letter of the last lending agency in the consortium shall be the relevant date.

- 6.3. In each of the above cases CIS will be disbursed in the account of the entity maintained with each lending agency on pro-rata basis.
- 6.4. The applicants who applied for UID under RRTUFS in i-TUFS software before the cutoff date i.e. 12 January 2016 but UIDs could not be issued to them for non availability of funds, will be given one time opportunity to apply for subsidy under ATUFS. They will be able to exercise this option on line within one month of receipt of communication to this effect from the Textile Commissioner.

7. Coverage of investment prior to sanction of the loan:

- 7.1. Advance payment up to the limit of his own share in the machine cost can be made by the applicant prior to the date of sanction of the term loan.
- 7.2. Machines purchased on or after the date of sanction of the term loan only shall be eligible for subsidy.
- 7.3. Purchase date shall be the date when full and final payment is made by the entity for machinery as evidenced by the bank transaction statement or the date of commercial invoice whichever is later.

8. Benefit under other schemes admissible:

Textile units are permitted to avail of benefits of State Government's Schemes, in addition to the benefit provided under this scheme.

9. Merger/ take-over of management of the entity:

In case of merger of the entities or take-over of an entity by another, the new entity will be entitled to get the subsidy, if due, under the scheme subject to the condition that the merger/ take over is either permitted by the Registrar of the Companies or by an order of the Court and the new entity has taken over all the liabilities and assets of the merged/ taken over entity and the respective bank has also transferred the term loan of the earlier entity in the name of the existing entity which has taken over. In such cases, the new entity shall submit a request in the prescribed format as per **Annexure–C** with all the supporting documents to the Textile Commissioner for changing the profile of the merged entity in i-TUFS software.

10. Implementation mechanism:

The scheme would be implemented by the Textile Commissioner through robust web based software called i-TUFS. Steps involved in implementation of the scheme are indicated below:

10.1. UID generation process:

- 10.1.1. The entity will register in i-TUFS software with the email, mobile number and PAN details through his authorized applicant.
- 10.1.2. The applicant will fill up the information as required in the system and apply for the term loan from the lending agency notified under the ATUFS.
- 10.1.3. List of notified lending agencies will be given in the information page of i-TUFS and will also be available in the dropdown menu in the application page of i-TUFS portal. The following shall be ensured while applying for the loan:
 - i. Tenure of the loan shall be a minimum of three years including moratorium period for MSME units and 5 years for other categories of entities.
 - ii. Loan shall be minimum 50% of the total eligible machinery cost. List of eligible prescribed specification of technology for all segments will be available in drop down menu of the i-TUFS portal. Besides, the indicative list of the manufacturers will also be available in drop down menu along with the provision of others to accommodate the machinery purchase from outside the indicative list.
 - iii. As this list is dynamic, the TAMC will update it every month and this list will be dynamic, the software team will keep on updating the list every month in sync with the TAMC decisions.
- 10.1.4. The application shall be signed off with the digital signature/ Aadhaar based e- sign of the applicant. An ATUFS Reference number will be generated for the application and communicated on the mobile number and email.

- 10.1.5. The application will be received in the INBOX of the lending agency with an SMS and email trigger. Lending Agency will scrutinize the proposal as per their norms, and if, found the project viable, sanction the term loan keeping in view the financial norms under ATUFS as stipulated in Para 5 of the guidelines.
- 10.1.6. Lending agency will fill in the details of the term loan information in i-TUFS and upload the copy of the final sanction letter with the digital signature of the authorized signatory of the lending agency. An SMS and email will go to the entity about sanction of term loan.
- 10.1.7. After sanction of the loan the application will reach INBOX of Textile Commissioner and UID will be generated automatically. The entity will be informed about the UID on their registered email and mobile number.
- 10.1.8. In case of rejection of loan application, information will be sent to the entity on their registered communication details. Any grievance at this stage may be taken up with the lending agency directly. Textile Commissioner will not be responsible for the grievances concerning with lending agencies.
- 10.1.9. Lending agency will endeavor to complete the process of sanction of term loan within 4 months of receipt of the application. Fortnightly email and SMS reminders will be sent to the lending agency.
- 10.1.10. Application can also be filed after sanction of term loan by the notified lending agency. In such case, the applicant shall directly apply for UID in i-TUFS maximum within six months of sanction of the term loan.
- 10.1.11. Applicant will register in i-TUFS software with his email, mobile number and PAN details. He will fill up the information as required in the system and sign off with his digital signature/ aadhaar based e-sign.
- 10.1.12. The application will go to the concerned lending agency for verification of the project and loan details. Lending agency will verify the application against the loan documents available with them; upload copy of the final loan sanction order and sign off the verification with the digital signature of the authorized official of the lending agency. The Lending Agency will endeavor to complete the exercise within 2 months of receipt of the application.
- 10.1.13. In case any discrepancy is observed in the information given by the applicant and the lending agency, the same will be resolved by the O/o Textile Commissioner by taking relevant evidence from the applicant and will intimate the Lending Agency if needed.
- 10.1.14. Applications successfully verified by the lending agency will reach inbox of Textile Commissioner and UID will be generated automatically. The entity will be informed about the UID on their registered email and mobile number.
- 10.1.15. UID will be a provisional approval for estimated subsidy. Actual subsidy will be decided on the outcome of Joint Inspection for which procedure is detailed in subsequent paras.
- 10.1.16. Applications which fail verification test at lending agency level, or during data quality check will be rejected. The entity will have the option to apply afresh. Any grievance at this stage may be taken up with the Textile Commissioner in the grievance module created in the i-TUFS. Textile Commissioner will dispose off the grievance within 30 days of receipt of the same.
- 10.1.17. To ensure that data error shall not creep in the system, i-TUFS software will provide a strong maker-checker, character control and other internal controls in software. However, applicant will have to ensure that the data is error free and all requisite documents are uploaded correctly. Error in the applications will lead to rejection of the application.

10.2. Installation of machinery:

- 10.2.1. Subsidy will be available only to the machinery meeting the technology parameters as specified under the scheme.
- 10.2.2. Only new machinery shall be installed. Second hand machinery will not be permitted under the scheme. Machine shall be purchased directly from the Original Equipment Manufacturer (OEM) or his authorized agent / supplier. In the latter case, a document showing that the Agent / Supplier is authorized by the manufacturer shall be required with the invoice.
- 10.2.3. Machine name and serial number should be expressly written on the Commercial Invoice/Bill of Lading/Airways Bill/Bill of Entry.
- 10.2.4. Model number and serial number of machinery shall be clearly indicated on the machine.
- 10.2.5. Installation and commissioning of the machinery covered under UID shall be done within one year from the date of sanction of term loan. Extension beyond one year may be permitted only on production of documentary proof that the order for machinery was placed within the prescribed timeline i.e one year from the date of sanction of term loan.

- 10.2.6. Request for JIT will be entertained if the machinery meets the technology specification but the manufacturer is not included in the indicative list. In such case, alert will be generated for the Textile Commissioner office to examine the eligibility of machinery to get included in the list and get it enlisted or rejected in the next monthly meeting of the Technical Committee. This exercise along with the approval of the TAMC should get completed within 45 days.
- 10.2.7. Fortnightly reminder mails and SMS will go to the entity to file JIT in time. If JIT request is not filed within the prescribed timelines or no request is made for extension, a system generated warning mail and SMS will go to entity 20 days before expiry of timeline that the UID will be canceled if JIT application is not filed within the deadline. UID will be automatically cancelled if request for Joint Inspection is not filed within the timeline and no further representation in this regard will be entertained.

10.3. Process to file application for Joint Inspection of the entity:

- 10.3.1 After installation of machinery entity will file online application for joint inspection.
- 10.3.2 The system will fetch all necessary information from UID of the entity. The applicant will provide following information against each of the machinery at the time of application for JIT:
- i. Make and model of the machinery
 - ii. SL. No of the machinery
 - iii. Basic cost of the machinery
 - iv. Basic cost of Accessories
 - v. Custom duty paid on machinery
 - vi. Date of purchase
 - vii. Proof of purchase (upload Payment receipt/ final invoice)
 - viii. Country of origin (In case of imported machines)
 - ix. Exporting country
 - x. Date of Bill of lading (Upload Bill of lading)
 - xi. Date of Bill of entry (Upload Bill of entry)
 - xii. Date of commissioning of machinery
 - xiii. Investment made in the project
 - xiv. Number of persons employed in project
 - xv. Bank statement showing the payment details
- 10.3.3 Addition or deletion of machinery data will be permitted at the time of JIT application.
- 10.3.4 Entity will also provide relevant information for Public Financial Management System (PFMS) registration at this stage for transfer of funds to the unit after JIT is approved.
- 10.3.5 Software will generate an MIC code for each machine as soon as the above information is provided in the system. MIC code shall be inscribed on the machines and to be verified by the Joint Inspection Team during physical inspection.
- 10.3.6 Through the MIC, details regarding segment, country of origin of machine, state/province code where machinery is installed, manufacturer code, authorized agent code, commercial invoice number, bill of entry, bill of lading, machine serial number etc can be deduced.
- 10.3.7 The applicant will sign off JIT application with his digital signature. The request will go to the concerned Regional Office (RO) of Textile Commissioner. The Textile Commissioner will constitute Joint Inspection Teams (JIT) under ROs of the Textile Commissioner having members from the lending agencies, Industry and from the Textile Research Association to physically verify installation and commissioning of the machineries and recommend eligible subsidy amount to the entity. JIT has to complete physical inspection within 88 days of application for Joint

Inspection.

10.4 Submission of JIT report

- 10.4.1 RO will provide report of Joint Inspection Team the same day or maximum the next day with geo-tagged and time stamped photographs in i-TUFS software. RO will also upload final copy of the invoice duly attested by him and sign off the verification with his digital signature.
- 10.4.2 The entity will have a view of their JIT report. The unit can represent to Textile Commissioner in case of disagreement with JIT report in the module created in i-TUFS within 15 days. Textile Commissioner will dispose off the representation within 30 days.
- 10.4.3 The Office of the Textile Commissioner will approve the subsidy claim maximum within 25 working days of filing of JIT report online by RO. For approving the subsidy, the enlistment of the manufacturer or his authorized agent/supplier will be essential.

10.5 Release of the eligible subsidy to the entity's account:

- 10.5.1 After approval by Textile Commissioner, automatic challan will be generated in i-TUFS.
- 10.5.2 Textile Commissioner will send the challan to the Ministry and Ministry will release the subsidy into the account of the entity within 15 working days of receipt of the Challan in the Ministry
- 10.5.3 Full amount will be released in case the applicant has taken loan from one lending agency under ATUFS. In case the applicant has availed down-selling of term loan or consortium financing, the subsidy amount will be credited into the account of the loanee on pro-rata basis.

11 Monitoring mechanism:

The scheme will be administered with a two stage monitoring mechanism i.e. by Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) and Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC).

11.1 Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC):

A Technical Advisory-cum-Monitoring Committee (TAMC) under the Chairpersonship of Textile Commissioner will be constituted with technical experts and the industry covering different segments. The composition and functions of TAMC are given at Annexure-D.

- 11.2 The TAMC will also monitor the progress of the scheme and apprise and advice the IMSC on all aspects of implementation of the Scheme.
- 11.3 Sample check of machinery shall be performed by the O/o the Textile Commissioner and the Ministry during the currency of project (Minimum specified duration is 3 years for MSME and 5 years for non MSME units) on a regular basis. Depending on the work load, a third party Engineering Consultant(s) may also be engaged with the approval of the Ministry for this purpose.

11.4. Inter-Ministerial Steering Committee (IMSC):

An IMSC will be constituted under the Chairpersonship of the Minister of Textiles with representatives from relevant Ministries, NITI Aayog, lending agencies, Textile Industry Associations etc. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the Cabinet Committee on Economic Affairs (CCEA)'s approval. The composition and functions of IMSC are given at Annexure-E.

- 11.5. The IMSC will review the progress of the scheme on half yearly basis and ensure its effective implementation.

12. Provisions for cancellation of UID:

- 12.1. UID issued under the scheme shall be cancelled in cases where the applicant fails to submit intimation of installation of the machinery within one year from the date of sanction of term loan for undertaking physical verification by a Joint Inspection Team (JIT) unless he is permitted for extension beyond one year by Textile Commissioner on the basis of sufficient documentary proof that the order for machinery was placed within time however installation and commission could not be completed due to circumstances beyond the control of the entrepreneur.

- 12.2. If the entity decides not to avail the subsidy under the scheme for any reason, it may request for cancellation of the UID in i-TUFS software.

13. Grievance Redress Mechanism:

- 13.1. i-TUFS has a grievance redress module. Grievances arising due to implementation of the scheme will be redressed by Textile Commissioner in 30 days.

14. Amendment of guidelines:

Any amendment of these guidelines involving financial issues may be done with the prior approval of the Expenditure Finance Committee (EFC). Amendment involving issues other than financial may be made with the approval of the IMSC and in case of urgency it can be amended with the approval of the Chairperson subject to ratification in the next meeting of the IMSC.

15. The resolution issued vide the order of even No dated the 29th February, 2016 on ATUFS will be superseded by this revised resolution.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

ORDERED also that copies of the Resolution may be communicated to the concerned Ministries / Departments / Organizations.

SANJAY SHARAN

Joint Secretary

Annexure - A

FORMAT FOR INCLUSION OF LENDING AGENCY UNDER ATUFS

(To be submitted to the Textile Commissioner through i-TUFS software)

| | | |
|----|----------------------------|--|
| 1. | Name of the Bank | |
| 2. | Address | |
| 3. | Name of the Contact Person | |
| 4. | Contact No. (O) | |
| 5. | Mobile No. | |
| 6. | e-mail I.D. | |
| 7. | Fax No. | |

Signature

Date:

Name & Designation with Seal

List of enclosures :

1. Copy of Banking Licence issued by RBI under Banking Regulation Act, 1949.
2. Copy of letter issued by RBI for inclusion in the second schedule to the RBI Act, 1934.
3. Copy of letter issued by GOI for registration under Multi State Cooperatives Act, if applicable.
4. Copy of PAN/TAN No.
5. Copies of Audited Balance Sheet for the preceding 3 years.

6. Other relevant information, if any.

Annexure -B

NO MULTIPLE FINANCING UNDERTAKING

(On the letter head of unit)

Date:

The _____(Name of the entity) hereby certify that no machinery or any part thereof, for which benefits are claimed under ATUFS has availed loan from more than once from this bank and/or any other bank(s)/Lending Agency(ies)/Financial Institution(s).

Following are the details of all project(s) undertaken and loans availed where benefits under TUFS have been availed by us:

| Sl. No. | NAME OF PROJECT | (PROJECT COST) | LOAN(S) TAKEN | LENDING BANK(S)/F.I.(S)/L.A.(S) |
|---------|-----------------|----------------|---------------|---------------------------------|
| | | | | |
| | | | | |
| TOTAL | | | | |

We also undertake that in the event of any inconsistency in the above mentioned facts, the entire subsidy along-with penal interest shall be reimbursed to the Government.

Signature of the authorized signatory of the entity

Name and Designation

* TUFS (Technology Upgradation Fund Scheme) means TUFS, MTUFS, RTUFS, RRTUFS and ATUFS

TUFS Ref. No. _____

Annexure C

Merger/take-over of Management of the Entity

| | Old Management | | | | New Managment | | | |
|----------------------|----------------|---------|---------|------------|---------------|---------|---------|------------|
| Name of the Entity | | | | | | | | |
| CIN No. | | | | | | | | |
| Details of Promoters | Name | Pan No. | DIN No. | Aadhar No. | Name | Pan No. | DIN No. | Aadhar No. |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| Loan Account No. | | | | | | | | |

| | | |
|-----------------------------|--|--|
| | | |
| Name of Lending Agency | | |
| IFSC Code of Lending Agency | | |

ANNEXURE – D**COMPOSITION OF TAMC**

| | | |
|-----|---|-------------|
| 1. | Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai | Chairperson |
| 2. | Director (ATUFS), Ministry of Textiles | Member |
| 3. | Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkata | Member |
| 4. | Industrial Adviser, Department of Heavy Industry, New Delhi | Member |
| 5. | Chairman, Confederation of Indian Textile Industry, New Delhi | Member |
| 6. | Chairman, Indian Woollen Mills Federation (IWMF), Mumbai | Member |
| 7. | Chairman, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry (FIASWI), Surat | Member |
| 8. | President, Indian Spinners Association (ISA), Mumbai | Member |
| 9. | President, South India Spinners Association (SISPA), Coimbatore | Member |
| 10. | President, Ludhiana Knitwear Club, Ludhiana | Member |
| 11. | Chairman, Textile Machinery Manufacturers Association of India (TMMAI), Mumbai | Member |
| 12. | President, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata | Member |
| 13. | Chairman, Clothing Manufacturers' Association of India (CMAI), Mumbai | Member |
| 14. | Chairman, Powerloom Development and Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai | Member |
| 15. | Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council (TEXPROCIL), Mumbai | Member |
| 16. | Chairman, Apparel Export Promotion Council (AEPC), Gurgaon | Member |
| 17. | Chairman, Synthetic and Rayon Textiles Promotion Council, Mumbai | Member |
| 18. | In-charge, TUFS Cell, IDBI Bank, Mumbai | Member |
| 19. | In-charge, TUFS Cell, Small Industries Development Bank of India (SIDBI), Lucknow | Member |
| 20. | Chairman, The Southern India Mills' Association, Coimbatore | Member |
| 21. | Chairman, Indian Technical Textile Association (ITTA), Mumbai | Member |
| 22. | In-charge, TUFS Cell, Industrial Finance Corporation of India, New Delhi | Member |
| 23. | In-charge, TUFS Cell, State Bank of India, Mumbai | Member |
| 24. | In-charge, TUFS Cell, Central Bank of India, Mumbai | Member |
| 25. | In-charge, TUFS Cell, Bank of India, Mumbai | Member |
| 26. | In-charge, TUFS Cell, NCDC, New Delhi | Member |
| 27. | In-charge, TUFS Cell, Bank of Baroda, Mumbai | Member |
| 28. | In-charge, TUFS Cell, Indian Overseas Bank, Mumbai | Member |
| 29. | In-charge, TUFS Cell, Union Bank of India, Mumbai | Member |

| | | |
|-----|---|------------------|
| 30. | In-charge, TUFS Cell, Punjab National Bank, New Delhi | Member |
| 31. | Director, Bombay Textile Research Association, Mumbai | Member |
| 32. | Addl./Joint Textile Commissioner in-charge of ATUFS, Office of Textile Commissioner, Mumbai | Member Secretary |

2. The TAMC will monitor and review the progress of the scheme including segmental progress and apprise the Ministry and the IMSC quarterly.
3. The TAMC will update and specify the eligible benchmarked machinery annually as on 1st April.

ANNEXURE – E

COMPOSITION OF IMSC

| | | |
|-----|---|---------------|
| 1. | Union Minister of Textiles | Chairperson |
| 2. | Secretary, Ministry of Textiles | Vice Chairman |
| 3. | Secretary, Department of Expenditure | Member |
| 4. | Secretary, Department of Financial Services | Member |
| 5. | Secretary, Department of Commerce | Member |
| 6. | Secretary, Department of Industrial Policy & Promotion | Member |
| 7. | Secretary, Department of Heavy Industry | Member |
| 8. | Secretary, Ministry of Micro, Small & Medium Enterprises | Member |
| 9. | Deputy Governor, Reserve Bank of India | Member |
| 10. | Addl. Secretary & Financial Advisor, Ministry of Textiles | Member |
| 11. | Textile Commissioner, Ministry of Textiles, Mumbai | Member |
| 12. | Jute Commissioner, Ministry of Textiles, Kolkatta | Member |
| 13. | Development Commissioner (Handlooms), New Delhi | Member |
| 14. | Adviser, (in-charge of the textiles), NITI Aayog, New Delhi | Member |
| 15. | Member Secretary, Central Silk Board, Bengaluru | Member |
| 16. | Chairman & Managing Director, IDBI | Member |
| 17. | Chairman & Managing Director, SIDBI | Member |
| 18. | Chairman & Managing Director, IFCI | Member |
| 19. | Chairman, State Bank of India | Member |
| 20. | President, Textile Machinery Manufacturers Association of India (TMMAI), Mumbai | Member |
| 21. | Chairman, Confederation of India Textile Industry (CITI), New Delhi. | Member |
| 22. | Chairman, Federation of India Art Silk Weaving Industry, Surat. | Member |
| 23. | Chairman, Indian Woolen Mills Federation (IWMF), Mumbai | Member |
| 24. | Chairman, Powerloom Development & Export Promotion Council (PDEXCIL), Mumbai | Member |

| | | |
|-----|--|------------------|
| 25. | Chairman, Indian Jute Mills Association (IJMA), Kolkata | Member |
| 26. | President, Clothing Manufacturers Association of India, Mumbai | Member |
| 27. | Chairman, Indian Technical Textile Association (ITTA), Mumbai | Member |
| 28. | Chairman, South India Spinners Association, Coimbatore | Member |
| 29. | Chairman, The Southern India Mills' Association, Coimbatore | Member |
| 30. | Additional /Joint Secretary (in-charge of ATUFS) | Member-Secretary |

2. IMSC would be responsible for monitoring and formulation of guidelines for effective implementation of the scheme in accordance with the CCEA approval. The IMSC will review the progress of the scheme half yearly and ensure its effective implementation.

3. Any amendment to the scheme involving issues other than financial may be made with the approval of IMSC.